संक्षिप्त समाचार

अनिल अग्रवाल की कंपनी की रेटिंग में सुधार, कर्ज कम करने पर है फोकस

नई दिल्ली, एजेंसी। माइनिंग से जुड़ी वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (वीआरएल) को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने रेटिंग में सुधार किया है। रेटिंग एजेंसी ने वीआरएल की कारोबारी परिवार रेटिंग को बी- (बी नकारात्मक) से बढ़ाकर बी कर दिया है। इसके साथ ही एसएंडपी द्वारा वीआरएल की रेटिंग पिछले साल दिसंबर के सीसी से पांच पायदान ऊपर हो गई है। एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सुधार वीआरएल द्वारा 2028 बॉन्ड के लिए अपनी सहमति निवेदन प्रक्रिया को बंद करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद आया है। बता दें कि कंपनी का अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने पर फोकस है। इसको देखते हुए अन्य प्रमुख रेटिंग एजेंसियां भी रेटिंग अपग्रेड कर रही हैं। वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज पिछले दो वर्षों में 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर घटा है। बीते दिनों वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन से समूह को ऋणमुक्त बनाने में मदद मिली। शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 20,639 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे अधिक एबिटा दर्ज किया। वेदांता का एल्यूमीनियम और जस्ता उत्पादन मात्रा के लिहाज से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले चार महीनों में वेदांता रिसोर्सेज ने बांड जारी करके 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, ब्याज लागत में 300 आधार अंक की कमी हासिल की है और अपनी ऋण परिपक्वताओं को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे कंपनी की पूंजी संरचना को काफी मजबूत करने में मदद मिली है।

जमा रकम पर ब्याज दर के नियमों का उल्लंघन, आरबीआई ने इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिपॉजिट पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडसइंड बैंक को आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण के बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया था। इंडसइंड बैंक के जवाब एवं अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत खाते खोलने से संबंधित आरोप सही साबित हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य इंडसइंड बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

दुबई से सोना खरीदने के दिन लद गए! अब भारत में ही सस्ती हुई गोल्ड ज्वैलरी

नई दिल्ली, एजेंसी। एक समय था जब दुबई में सोना खरीदना भारत के मुकाबले काफी सस्ता होता था। लेकिन अब सीन बदल गया है। दुबई के मुकाबले भारत में सोने के आभूषण खरीदना सस्ता हो गया है। शायद यही कारण है कि दुबई में रहने वाले एनआरआई अब भारत में ही गोल्ड ज्वैलरी के ऑर्डर दे रहे हैं। इससे स्थानीय ज्वैलर्स की बिक्री काफी बढ़ गई है। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सोने पर कस्टम ड्यूटी में कटौती और यहां गोल्ड ज्वैलरी पर लगने वाले कम मेकिंग चार्ज के चलते भारत में सोने की कीमत काफी कम हुई है। प्रमुख आभूषण विक्रेताओं ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान एनआरआई खरीद में एक साल पहले की तुलना में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दो महीनों में बिक्री 80 टन तक पहुंचने की संभावना है।

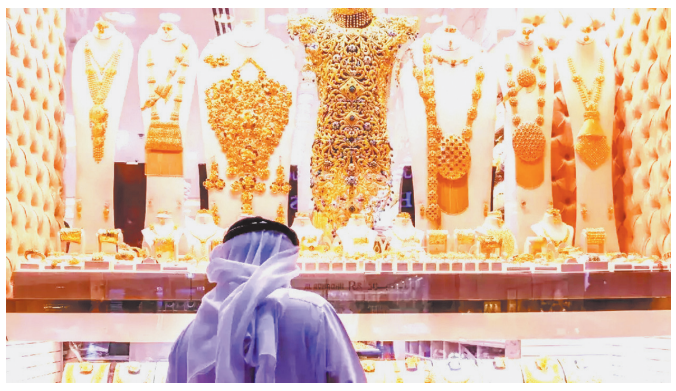

भारत में कम हुई सोने की कीमत

एनआरआई और भारतीय पर्यटक दुबई से सोना खरीदकर लाना पसंद करते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पहले सोना खरीदना भारत के मुकाबले काफी सस्ता था। लेकिन अब मामला पलट गया है। एनआरआई अब भारत में ही स्थानीय ज्वैलर्स को ज्वैलरी के ऑर्डर दे रहे हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि जुलाई में बजट के दौरान सोने पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई थी। इस कटौती के बाद कीमतों में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर भारत में ज्वैलरी बनाने का शुल्क भी बहुत कम है। यह दुबई के मुकाबले करीब आधा है।

दुबई में कारोबार पर पड़ा असर

सोने की ज्वैलरी बनाने वाली एक नामचीन चेन के चेयरमैन जॉय अलुकास ने कहा कि इस शादी के मौसम (15 नवंबर से 15 दिसंबर) में सोने की बिक्री बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एनआरआई की ओर से भारत में इनके स्टोर पर सोने की ज्वैलरी की खरीद में पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं सितंबर तिमाही में सोने की मांग में पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, इसके विपरीत, हमारे दुबई आउटलेट पर बिक्री कम हो गई है क्योंकि अधिकांश एनआरआई अब भारत से सोने के आभूषण खरीदना पसंद कर रहे हैं। कोच्चि स्थित इस चेन के 160 स्टोर हैं, जिनमें से 35 आउटलेट दुबई में हैं।

कितना टैक्स और कितना मेकिंग चार्ज?

दुबई सोने के आभूषणों पर 5 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाता है। वहीं भारत ने ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब है कि दुबई में लगने वाला वैट अभी भी ज्यादा है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के उपाध्यक्ष राजेश रोकड़े ने कहा, भारत में सोने से ज्वैलरी बनाना काफी सस्ता है। दुबई में मेकिंग चार्ज जहां 25 से 35 प्रतिशत है तो वहीं भारत में यह 10 से 20 प्रतिशत है।

970 तक जा सकता है टाटा मोटर्स का शेयर, 30 प्रतिशत डिस्काउंट पर कर रहा कारोबार

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच शुक्रवार को टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर भी दबाव में नजर आए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन टाटा मोटर्स के शेयर 2.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 724 रुपये पर बंद हुए। शेयर का यह भाव अपने 52 वीक के हाई यानी 1,179.05 रुपये से लगभग 38 प्रतिशत डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बता दें कि शेयर 30 जुलाई 2024 को भी 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया था। वहीं, इस शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज एलकेपी सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स के शेयर को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि घरेलू कॉमर्शियल व्हीकल्स (सीवी) की मांग दूसरी छमाही में बढ़ सकती है और हालिया लॉन्चिंग से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। घरेलू ब्रोकरेज ने शेयर पर 970 रुपये का नया टारगेट प्राइस सुझाया है, जो वर्तमान कीमत से 30 प्रतिशत अधिक है। हाल ही में टाटा मोटर्स को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) से 1,297 बस चेसिस का ऑर्डर मिला है।

संभलकर करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, डिफॉल्ट हुए तो 50 प्रतिशत तक देना होगा ब्याज

नई दिल्ली, एजेंसी। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा शेर है जिसे काबू में रखा जाए तो ठीक है। अगर यह बेकाबू हुआ तो बड़ी मुसीबत बन जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न चुकाने पर बैंक बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं। यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत पहुंचा था जहां ब्याज दर को 30 फीसदी तक सीमित कर दिया था। लेकिन अब नेशनल कंज्यूमर फोरम के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनसीडीआरसी ने अपने एक फैसले में कहा था कि क्रेडिट कार्ड पर उपभोक्ताओं से 36 से 50 फीसदी सालाना ब्याज लेना बहुत ज्यादा है। एनसीडीआरसी ने इसे गलत कारोबारी प्रथा बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इससे बैंकों को राहत मिली है। बैंक अब क्रेडिट कार्ड पर 30 फीसदी से ज्यादा यानी 50 फीसदी तक ब्याज ले सकेंगे।

क्या कहा था एनसीडीआरसी ने

उपभोक्ता अदालत ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर को अधिकतम 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया था। उपभोक्ता आयोग ने माना था कि बैंकों और उपभोक्ताओं के बीच समझौता असमान स्थिति में होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए उपभोक्ताओं के पास कोई मोलभाव की शक्ति नहीं होती, सिवाय इसके कि वे क्रेडिट कार्ड की सुविधा को अस्वीकार कर दें। आयोग ने यह भी कहा था कि अगर उपभोक्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल होने पर अत्यधिक जुर्माना देना पड़े तो यह अनुचित व्यापार प्रथा मानी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता अदालत ने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों की तुलना विभिन्न देशों से की थी।

विदेशों का दिया था हवाला

अपने फैसले में एनसीडीआरसी ने कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन में ब्याज दर 9.99 प्रतिशत से 17.99 प्रतिशत फीसदी के बीच है। ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत फीसदी है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मेक्सिको (उभरती अर्थव्यवस्थाएं) में ब्याज दर 36 प्रतिशत से 50 प्रतिशत फीसदी है। भारत जैसे बड़े और विकासशील देशों में उच्चतम दर अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। आयोग ने क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों पर 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा तय करते हुए कहा था कि 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर को अत्यधिक माना जाएगा। यह अनुचित व्यापार प्रथा के तहत आएगा। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 2008 के आदेश को रद्द कर दिया और बैंकों द्वारा दायर सभी दीवानी अपीलों को मंजूरी दे दी।

यूबीएस: भारत को लेकर सतर्क, चीन को ज्यादा तरजीह...

नई दिल्ली, एजेंसी। यूबीएस ने भारतीय बाजार को लेकर फिलहाल सतर्क रुख अपनाया हुआ है। कमजोर कमाई और सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते उसे बाजार महंगा लग रहा है। इसके उलट यूबीएस चीन के बाजार को ज्यादा तरजीह दे रहा है। वहां प्रोत्साहन पैकेज और नीतिगत घोषणाओं से बाजार को बल मिलने की उम्मीद है। दुनिया की प्रमुख फाइनेंशियल कंपनी का मानना है कि भारत में नौकरियों और आय में बढ़ोतरी होना जरूरी है। इस तरह की कुछ दिक्कतें दूर हो जाएं तो भारत में बंपर संभावनाएं हैं।

यूबीएस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्ट सुनील तिरुमलाई ने वैश्विक बाजारों और भारत की आर्थिक स्थिति पर अपनी राय दी है। उन्होंने बताया कि कमजोर कमाई और सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते भारत महंगा लग रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। यह बात खासतौर से उभरते बाजारों के लिए है। ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी, ऊंचे वैल्यूएशन और बढ़ती ब्याज दरें बाजारों में निवेश के लिए चुनौतियां पेश कर रही हैं। यूबीएस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए 2025 में गिरावट की आशंका जता रहा है। भारत में उनका निवेश कम है। जबकि चीन में ज्यादा। कारण है कि वहां के प्रोत्साहन पैकेज और आकर्षक मूल्यांकन उसे लुभा रहे हैं। हालांकि, अगर चीन में उम्मीद के मुताबिक हालात नहीं रहे तो रणनीति बदल सकती है।

तिरुमलाई ने बताया कि भारत में कुछ क्षेत्र जैसे उपभोक्ता वस्तुएं और आईटी सेवाएं अभी भी आकर्षक हैं। चीन के अलावा अन्य देशों में उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन, भारत को इसमें सफल होने के लिए और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। नए जमाने की तकनीकी कंपनियों में निवेश की संभावनाएं हैं, लेकिन जोखिम भी हैं। बाजार में बड़े बदलाव के लिए भारत की अपनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों का लिस्ट होना जरूरी है। तिरुमलाई का मानना है कि रोजगार और आय में बढ़ोतरी होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।

सुनील तिरुमलाई ने वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, 2025 बहुत अनिश्चित होगा और यह आम तौर पर बाजारों के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उभरते बाजारों, खासकर एशिया के लिए कई चुनौतियों का जिक्र किया। ट्रंप प्रशासन की नीतियां, जैसे अमेरिका के बाहर कई देशों पर टैरिफ लगाना और अमेरिकी कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती, इन चुनौतियों में शामिल हैं। इससे अमेरिकी बाजार में निवेश आकर्षक हो सकता है। इससे बाकी दुनिया से पैसा निकलकर वहां जाने के आसार हैं।

इसके अलावा, तिरुमलाई ने ऊंचे वैल्यूएशन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मूल्यांकन न केवल भारत के लिए बल्कि श्वरू स्तर पर भी 10-12 साल की अवधि में काफी ऊंचे स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में कमजोर कमाई और सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण भारत महंगा लग रहा है। चीन प्लस वन रणनीति पर तिरुमलाई ने कहा कि इस बारे में सोच बदल रही है। उन्होंने कहा, हाल ही में ट्रंप ने भी कहा है कि वह न केवल चीन पर, बल्कि अन्य बाजारों पर भी टैरिफ के बारे में बात करते हैं। इसलिए, अगर टैरिफ लेनदेन पर आधारित बातचीत का साधन बन जाता है तो यह तय नहीं है कि चीन के बाहर फैक्ट्रियों का ट्रांसफर स्थायी होगा। कंपनियां अन्य जगहों पर जाने के बजाय अमेरिका में ही अधिक फैक्ट्रियां स्थापित करना चाह सकती हैं।

भारत पर अंडरवेट रुख के बारे में तिरुमलाई ने कहा कि वे जिन कारकों पर नजर रखेंगे उनमें मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर प्रमुख है। उन्होंने कहा, हमें नौकरियों और आय में बढ़ोतरी के मजबूत संकेत देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हो जाने पर बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब व्यवसायों को अच्छी मांग दिखाई देगी। वे निवेश करना शुरू कर देंगे और खपत बढ़ने लगेगी। उन्होंने कहा कि इस समय यूबीएस चीन पर ओवरवेट हैं। यानी उसे अधिक तरजीह दी हुई है। वहां प्रोत्साहन पैकेज और नीतिगत घोषणाओं के साथ आकर्षक वैल्यूएशन निवेश को खींच रहे हैं। तिरुमलाई ने कहा कि ट्रंप का एक और सकारात्मक फैक्टर तेल की कीमतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा, अतीत में उन्होंने अमेरिका से अधिक तेल पंप करने का जिक्र किया है। इससे तेल की कीमतें कम हो सकती हैं।

बिजली वितरण कंपनियां राज्यों पर वित्तीय रूप से बोझ बनीं, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही यह बात

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) राज्यों के लिए वित्तीय रूप से भारी बोझ बनी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य डिस्कॉम का कुल संचित घाटा 2022-23 तक 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, ÷बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) राज्यों पर वित्तीय रूप से बोझ बनी हुई हैं।÷ रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न सुधार प्रयासों के बावजूद डिस्कॉम राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। हालात बदलने के लिए, आरबीआई ने उत्पादकता में सुधार, ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को कम करने और बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत के साथ टैरिफ को एडजस्ट करने जैसे उपायों के महत्व पर जोर दिया।

नवरत्न कंपनी को मिला 300 करोड़ रुपये का काम, शेयर का भाव 100 रुपये से कम

नई दिल्ली, एजेंसी। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने शुक्रवार को नए वर्क ऑर्डर की जानकारी दी। कंपनी ने 20 दिसंबर को बताया कि उन्हें कई ऑर्डर मिले हैं। जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपये का है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयर बाजार के बंद होने के समय पर 2.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 94.44 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी ने बताया है कि उन्हें 200.60 करोड़ रुपये का काम ऑयल इंडिया लिमिटेड से मिला है। कंपनी को ऑयल हॉस्पिटल बनाना है। इसके अलावा एचएससीसी (इंडिया) को 98.17 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह एनबीसी की सब्सिडियरी कंपनी है। बता दें, इसी महीने के शुरुआत में 600 करोड़ रुपये का काम एनबीसीसी को मिला था। कंपनी की आर्थिक स्थिति की बात करें सितंबर तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 125.10 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर एनबीसीसी लिमिटेड के नेट प्रॉफिट में 52.80 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 81.90 करोड़ रुपये रहा था।

नौकरी छोड़ बन गए कारोबार के द्रोणाचार्य, उंगलियों पर टिप्स सिखा बनाई पहचान

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में पले-बढ़े डॉ. मानव आहूजा अब इंटरनेशनल बिजनेस गुरु कहलाते हैं। दुबई में नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पहचान बनाई है। मानव आहूजा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है। उन्होंने टीपीईजी इंटरनेशनल एलएलसी की नींव रखी। यह कंपनी दुनियाभर के युवाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद करती है। उनका टारगेट 2025 तक 10,000 भारतीय ब्रांड्स को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाना है। आइए, यहां मानव आहूजा की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

पढ़ाई के बाद दुबई में की नौकरी

डॉ. मानव आहूजा की कहानी संघर्ष और सफलता की मिसाल है। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले मानव ने अपनी शुरुआती शिक्षा डॉ. राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल और खालसा स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। बिजनेस मैनेजमेंट में दिलचस्पी के चलते उन्होंने मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया। बेहतर करियर अवसरों की तलाश में मानव दुबई चले गए। वहां उन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सेल्स एक्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। दुबई में जीवन आसान नहीं था। नया माहौल, नई चुनौतियां, सब कुछ उनके लिए अलग था। लेकिन, मानव ने हार नहीं मानी। 48-52 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उन्होंने मार्केटिंग का काम किया। क्लाइंट्स से मिलने के लिए कड़ी धूप में यात्रा करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें व्यापार की दुनिया की गहरी समझ दी।

मानव को दुबई में कठिन दौर से भी गुजरना पड़ा। एक बार उन्हें संक्रमण हो गया। उनके पास दवाओं के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके रूममेट ने उनकी मदद की। इस मुश्किल समय से उबरने के बाद मानव ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। मानव ने अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करके दूसरों को व्यापार की ट्रेनिंग देना शुरू किया।

अपनी कंपनी की रखी नींव

मानव आहूजा ने टीपीइजी इंटरनेशनल एलएलजी की स्थापना की। यह कंपनी उन युवाओं को मार्गदर्शन देती है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आज उनकी कंपनी दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। मानव अब इंटरनेशनल बिजनेस गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी उन युवाओं को प्रेरित करती है जो नौकरी के अलावा अपना खुद का काम करना चाहते हैं।

बड़ा है टारगेट

डॉ. मानव अहूजा टीपीइजी इंटरनेशनल एलएलजी के संस्थापक होने के साथ कोच और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भारत, श्रीलंका, अफ्रीका और कई अन्य देशों में व्यवसायों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने का 25 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। प्रबंधन परामर्श, टीम प्रशिक्षण और बाजार विस्तार का गुर सिखाने में डॉ. मानव की महारत है। उन्होंने कई उद्यमियों को अभूतपूर्व सफलता हासिल करने में मदद की है। 2025 तक उनका टारगेट 10,000 भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का है। डॉ. मानव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से कुछ भी असंभव नहीं है।

आर्थिक मंदी पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की जरूरत, बोले आरबीआई के एमपीसी सदस्य नागेश कुमार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीस) के सदस्य नागेश कुमार के अनुसार देश में चल रही आर्थिक मंदी इस हद तक गंभीर हो गई है, जिसपर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। दिसंबर एमपीसी बैठक के दौरान रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की वकालत करते हुए , कुमार ने घटती वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं की दोहरी चुनौतियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी बैठक के मिनटों के अनुसार, इसके सदस्य नागेश कुमार ने जोर देकर कहा कि अक्तूबर 2024 की एमपीसी बैठक के बाद से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कुमार ने भारत की आर्थिक वृद्धि में भारी गिरावट की ओर इशारा किया। 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी विकास दर उसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत और 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई है। कुमार ने कहा कि यह गिरावट अपेक्षा से अधिक तेज है और इसने वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमानों में व्यापक कटौती करवा दी है।कुमार ने तर्क दिया कि 25 आधार अंकों की दर में कटौती मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि कीमतों में मौसमी सुधार के साथ मुद्रास्फीति के दबाव कम हो सकते हैं, जिससे सहायक नीति उपायों के लिए जगह बन सकती है।